

प्रेषक,

आर०डॉ०पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 28 सितम्बर, 2007

विषय: मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के हल्द्वानी स्थित गेस्ट हाउस की छत एवं फर्श बदलने, अतिरिक्त टायलेट व पर्शों के कार्य एवं अतिरिक्त कक्ष के फर्श बदलने से सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि को स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3519/UHC/Admin.B/Const./2007, दिनांक 3.8.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के हल्द्वानी स्थित गेस्ट हाउस की छत एवं फर्श बदलने, अतिरिक्त टायलेट व पर्शों के कार्य एवं अतिरिक्त कक्ष के फर्श बदलने से सम्बन्धित कार्य हेतु रु० 17.65 लाख + 0.54 लाख = 18.19 लाख के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 15,40,000 + 48,000 = 15,88,000/- (पन्द्रह लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 8,76,000/- (आठ लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल विम्वन शर्मा के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विरलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, को स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं सांक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

- (7) कार्य करते समय यह सुनिश्चित करले कि अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।
  - (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री को किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।
  - (9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर चैजर्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर किये गए आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशामी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
  - (10) स्वोक्त की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वोक्त धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 को आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुरक्षण" के नामे हाता जायेगा ।
- 4.- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अग्रसूची संख्या-930/XXVII(5)/2007, दिनांक 24.9.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( आर०डी०पालीवाल )  
सचिव ।

संख्या-30-दो(8)/XXXVI(1)/2007-24-दो(8)/07-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, नैनीताल ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशामी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव ।